बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 223099 पटना, दिनांक 09-03-2015

ग्रा.वि.14(भा0)बांका0-01/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री श्रीनिवास सिंह,
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, शम्भूगंज, बांका,
सम्प्रति उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।

नेबंधित/चपरासी बही

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बांका से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जिला में विषयांकित अवधि में आप शम्भूगंज प्रखंड (जिला-बांका) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, बाँका से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
108.92	149220.400/-

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 108.92 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं आपका उत्तरदायित्व निर्धारण कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक- यथोक्त।

(प्रदीप कुमार) 4.3.15
सचिव

Yearwise Report of SGRY Grains for Block Wise/Dealer Wise

Year	Name of BDO	Name of Dealer	Alloted Quantity	Lifted Qty.	Distributed Qty.	Lifted but not Distributed	Per Quintal rate at which recovery is being attempted	Total amount recoverable (10*11)	Total amount recovered	Balance Amount (12-13)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	श्री राम कु0 सिंह	श्री संजय तिवारी	2427.540	1285.740	1285.740	0.000	1761463.8	1761463.8	0	0	
2004-05	श्री राम कु0 सिंह	श्रीकांत मिश्र	770.960	770.960	770.960	0.000	1056215.2	1056215.2	0	0	
2004-05	श्री कारी प्र0 महतो	श्रीकांत मिश्र	4172.080	4172.080	4172.080	0.000	5715749.6	5715749.6	0	0	
2004-05	श्री कारी प्र0 महतो	श्रीकांत मिश्र	1352.520	1352.520	1352.520	0.000	1852952.4	1852952.4	0	0	
2004-05	श्री सियाराम सिंह	श्री अमीत कुमार साह	3786.170	317.490	317.490	0.000	434961.3	434961.3	0	0	
2004-05	श्री सियाराम सिंह	श्री संजय तिवारी	1195.060	1195.060	1195.060	0.000	1637232.2	1637232.2	0	0	
2004-05	श्री सियाराम सिंह	श्री विभीषण कुमार	3864.520	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	
2004-05	श्री सियाराम सिंह	श्री संजय तिवारी	1248.660	1248.660	[illegible]	0.000	[illegible]	1710664.2	0	0	
2004-05	श्री विनय कु0 मंडल	श्री विभीषण कुमार	2218.240	294.010	294.010	0.000	402793.7	402793.7	0	0	
2004-05	श्री विनय कु0 मंडल	श्री विभीषण कुमार	663.350	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	
2004-05	श्री आशीष कु0 सिन्हा	श्री विभीषण कुमार	3580.120	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	
2004-05	श्री आशीष कु0 सिन्हा	श्री संजय तिवारी	1164.930	783.990	783.990	0.000	1074066.3	1074066.3	0	0	
2004-05	मो0 शहाबउद्दीन	श्री संजय तिवारी	2878.160	1432.170	1432.170	0.000	1962072.9	1962072.9	0	0	
2004-05	मो0 शहाबउद्दीन	श्री संजय तिवारी	890.260	890.260	890.260	0.000	1219656.2	1219656.2	0	0	
2004-05	श्री आलोक कुमार	श्री विभीषण कुमार	3623.330	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	
2004-05	श्री आलोक कुमार	श्रीकांत मिश्र	1163.690	711.495	711.495	0.000	974748.15	974748.15	0	0	
2004-05	श्री प्रभात कु0 झा	श्री अमीत कुमार	3361.430	1944.740	1944.740	0.000	2664293.8	2664293.8	0	0	
2004-05	श्री प्रभात कु0 झा	श्री अमीत कुमार	1011.420	987.740	987.740	0.000	1353203.8	1353203.8	0	0	
2004-05	श्री निवास सिंह	मो0 असीरउद्दीन अंसारी	3647.670	986.250	877.330	108.920	1351162.5	1201942.1	149220.4	149220.4	
कुल :-			43020.110	18373.165	18264.245	108.920	25171236.050	25022015.650	149220.400	149220.400	

21/11/14
सहायक परियोजना पदा०,
डी० आर० डी० ए०, बाँका
21/11/14

निदेशक
जि० ग्रा० वि० अभि०, बाँका

उप विकास आयुक्त
बाँका

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementotion of NREGA in Districts identified.*

Sir/Madam.

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
प्राप्ती संख्या ....
दिनांक

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP ... completed upto 30.6.2006 ...

... provided. The foodgrains authorization ... would terminate ... grains ... year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8 In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक ________/ग्रा०वि०पटना, दिनांक-
8(विविध)40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।